लेटर्स पेटेंट अपील

दया कृष्ण महाजन और गुरदेव सिंह जे. के समक्ष

जीवनधर कुमार,-अपीलकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, प्रतिवादी।

लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 338 आफ 1967

फ़रवरी 19, 1968.

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम (1947 का VII)–एस. 31-पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967, खंड I, अध्याय IV-विनियम 10 और 22- एक विनियमन का संचालन-सरकार की पूर्व मंजूरी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन-चाहे आवश्यक हो-विनियमन के संशोधन के लिए विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी की परीक्षा शुरू होने से पहले 10-परीक्षा के समापन के बाद सरकार की मंजूरी-परीक्षा की छूट की घोषणा के बाद आधिकारिक राजपत्र में संशोधन का प्रकाशन-विनियम 10 का ऐसा संशोधन-क्या उक्त परीक्षा पर लागू होता है।

माना गया कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 31 के मद्देनजर, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के पास न केवल किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। मैट्रिक परीक्षा, बल्कि किसी नियम या विनियम या उपनियम में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करना भी। अधिनियम की धारा 31 के तहत विनियम तैयार करने की प्रक्रिया पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967, खंड I के अध्याय IV में प्रदर्शित विनियमों में निहित है। इन प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि सीनेट द्वारा तैयार किए गए विनियम लागू होने से पहले या लागू किया जा सकता है, धारा 31 के तहत सरकार से इसकी मंजूरी प्राप्त करनी होती है, और इसे विनियमन 22 में दिए गए अनुसार राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। राजपत्र में इसके प्रकाशन पर ही कोई विनियमन प्रभावी होता है।
माना गया कि यह सच है कि इस मामले में सीनेट ने अपीलकर्ता की परीक्षा शुरू होने से पहले दिसंबर, 1966 में विनियमन 10 के संशोधन को मंजूरी दे दी थी, और इसके द्वारा अनुमोदित संशोधित विनियमन में कहा गया था कि यह परीक्षा से प्रभावी होगा 1967, फिर भी तथ्य यह है कि अप्रैल 1967 में अपीलकर्ता की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला था कि संशोधित विनियमन को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, और बाद में, अपीलकर्ता का परिणाम घोषित होने के बाद, यह संशोधित विनियमन आया , जिसके आधार पर उसे असफल बताया गया है, प्रकाशित किया गया था। चूंकि यह केवल विनियम के प्रकाशन पर ही लागू होता है, जैसा कि

विनियम 22 में प्रदान किया गया है, यह राजपत्र में इसके वास्तविक प्रकाशन से पहले परिणाम घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, जब इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था। 1967 के सिविल रिट संख्या 1335 में पारित माननीय श्री न्यायमूर्ति टेक चंद के आदेश, दिनांक 5 सितंबर, 1967 के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील।

याचिकाकर्ता के लिए एम. एस. जैन, वकील जी. एस. चावला के साथ:
एच.आर. सोढ़ी, वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं के लिए एन.के. सोढ़ी, वकील के साथ।

निर्णय

गुरदेव सिंह, जे.-

लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपीलकर्ता द्वारा लाए गए 1967 के सिविल रिट संख्या 1335 में 5 सितंबर, 1967 को पारित किया। अपीलकर्ता जीवनधर कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज, हिसार का छात्र, अप्रैल, 1967 में पंजाब विश्वविद्यालय की प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में उपस्थित हुआ। उस परीक्षा के परिणाम 14 जून, 1967 को प्रकाशित किए गए और याचिकाकर्ता को असफल घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी और गणित विषयों में उन्होंने 150 में से क्रमशः 48 और 50 अंक प्राप्त किए थे, जो कि प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय विनियमन 10 के तहत उत्तीर्ण अंकों के रूप में निर्धारित अधिकतम अंकों के 35 प्रतिशत से कम था। 10 दिसंबर, 1966 को पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट, और 5 अगस्त, 1967 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।
इसके संशोधन से पहले, यह विनियम 10 इस प्रकार पढ़ा गया: -

"परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों की न्यूनतम संख्या प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत होगी, बशर्ते कि प्रत्येक विज्ञान विषय में परीक्षा के लिखित और व्यावहारिक भागों में यह प्रतिशत अलग-अलग आवश्यक होगा:

आगे कहा गया है कि एक उम्मीदवार जो एक या एक से अधिक विषयों में कुल कुल अंकों (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) के एक प्रतिशत से अधिक से असफल होता है, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक दिए जाएंगे और ये उसके सर्वोत्तम लाभ के लिए होंगे। एक उम्मीदवार जो कंपार्टमेंट नियमों के तहत किसी विषय में उपस्थित होता है और विषय में कुल

अंकों के एक प्रतिशत से अधिक अंकों से असफल नहीं होता है, उसे उत्तीर्ण घोषित करने के लिए विषय के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक दिए जाएंगे। की परीक्षा पास की। एक उम्मीदवार को अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंकों के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक कि उसने कम से कम तीस-तीस प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए हों, जिस स्थिति में ये अंक कुल में जोड़े जाएंगे।

संशोधित विनियमन, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को असफल घोषित किया गया था, ने विनियमन के प्रारंभिक भाग में केवल "33" के स्थान पर "35" अंक को प्रतिस्थापित किया, बिना कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन किए। यह विवादित नहीं है कि इस संशोधित विनियमन (बाद में इसे नया विनियमन कहा जाएगा) के आधार पर अपीलकर्ता को प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता है। यह सच है, अपीलकर्ता ने अंग्रेजी में 150 में से केवल 48 अंक प्राप्त किए थे और इस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए, यहां तक कि संशोधन से पहले पुराने नियम 10 के अनुसार, उसे प्रत्येक में 33 प्रतिशत वी अंक प्राप्त करने थे। विषय, लेकिन यह विवादित नहीं है कि उस पुराने विनियमन के प्रावधान के तहत वह छह अनुग्रह-अंकों के लाभ का दावा कर सकता था और इस प्रकार उसे प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता। यह तर्क देते हुए कि नया विनियमन 10 उस पर लागू नहीं होता है और वह पुराने विनियमन द्वारा शासित होता है, अपीलकर्ता 14 तारीख को घोषित उसके परिणाम को रद्द करने के लिए रिट याचिका के साथ इस न्यायालय में आया था, जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई है। जून, 1967, और यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई कि उन्होंने अप्रैल, 1967 में आयोजित प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और प्रतिवादी विश्वविद्यालय को उन्हें बी.एससी. में प्रवेश देने का निर्देश दिया जाए। (टी.डी.सी. भाग II;), या किसी अन्य वर्ग के लिए जिसके लिए वह प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर पात्र पाया गया था। उनकी याचिका का प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की ओर से इस दलील पर विरोध किया गया था कि वह नए विनियमन 10 द्वारा शासित थे और दो विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने के कारण, उन्हें हटा दिया गया था। प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में असफल घोषित किया जाना सही है। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष निर्णय के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या यह पुराना विनियमन 10 था या नया विनियमन था जो उसके मामले को नियंत्रित करता था और जिसके आधार पर उसका परिणाम घोषित किया जाना था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि चूंकि नए विनियमन को अप्रैल, 1967 में आयोजित परीक्षा पर लागू करने के लिए पूर्वव्यापी बनाया गया था, याचिकाकर्ता नए के तहत निर्धारित अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक हासिल करने में असफल रहा। विनियमन को ठीक ही विफल घोषित कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि "पंजाब विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के ऐसे किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया है जिसे परमादेश की रिट जारी करके लागू किया

जा सकता है", और कहा "विश्वविद्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के चार कोनों के भीतर काम किया और नया विनियमन जिसे पूर्वव्यापी बनाया गया था, उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।" इस प्रकार अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई।

अपील के तहत आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एम.एस. जैन ने दलील दोहराई है कि अपीलकर्ता का मामला पुराने विनियमों द्वारा शासित था और पुराने विनियम 10 के प्रावधानों के अनुसार था जैसा कि पहले था। संशोधन के बाद, वह छह अनुग्रह-चिह्नों का हकदार था और इस प्रकार वह पारित घोषित होने का हकदार था। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए श्री एच.आर. सोढ़ी ने इस पर कोई विवाद नहीं किया है कि यदि पुराने नियम अपीलकर्ता के मामले को नियंत्रित करते हैं, तो वह अप्रैल, 1967 में आयोजित प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के हकदार थे। उन्होंने कहा, ' हालाँकि, आग्रह किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता नए विनियमन द्वारा शासित था, जिसके अनुसार उसे हर विषय में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे, सही था, और हस्तक्षेप का कोई भी मामला कोई अधिकार नहीं था। याचिकाकर्ता में निहित अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इस प्रकार, विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या नए विनियमन को अपीलकर्ता के मामले में उसके परिणाम घोषित करने में सही ढंग से लागू किया गया था।

इस मामले से निपटने से पहले, उस तरीके का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें संबंधित विनियमन में संशोधन किया गया और नया विनियमन 10 अस्तित्व में आया। 9 सितंबर, 1966 को, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने निर्णय लिया कि प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए निर्धारित विभिन्न विषयों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और अन्य संबंधित संशोधनों को प्रभावी बनाया जाए। वर्ष 1967 में आयोजित होने वाली परीक्षाएँ। इस प्रस्ताव को 17 सितंबर, 1966 को सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसे पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को प्रसारित करने के बाद, विनियमन में प्रस्तावित संशोधन को समक्ष रखा गया था। 19 सितंबर, 1966 को सिंडिकेट और बाद में 10 दिसंबर, 1966 को सीनेट द्वारा इसे विधिवत मंजूरी दे दी गई। इस बीच पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ और 11 जनवरी को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1967, नए विनियमन को पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया था।

“धारा 31. विनियम:

(1) सीनेट, सरकार की मंजूरी से, समय-समय पर, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से और व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
पूर्वगामी शक्ति, ऐसे विनियम प्रदान कर सकते हैं-

(एन) मैट्रिक परीक्षा के अलावा किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए, साथ ही डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि, सम्मान चिह्न, छात्रवृत्ति और पुरस्कार के लिए भी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदत्त;
(क्यू) धारा 40 के आधार पर इस अधिनियम के प्रारंभ में लागू पंजाब विश्वविद्यालय के किसी भी नियम, विनियम, क़ानून या उप-कानून में परिवर्तन या रद्दीकरण;

10 दिसंबर, 1966 को हुई बैठक में सीनेट द्वारा विनियमों में संशोधन को अपनाए जाने के बाद, उन्हें इसकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था। यह मंजूरी दिए जाने से पहले, प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की गईं और अपीलकर्ता ने उस परीक्षा के लिए निर्धारित सभी विषयों में विधिवत परीक्षा दी। हालाँकि, 16 मई, 1967 को, अपीलकर्ता की परीक्षा समाप्त होने के बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र द्वारा नए विनियमन पर अपनी सहमति दी, जिसकी प्रति प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अनुलग्नक के रूप में रखी गई थी। आर. 3. 5 अगस्त 1967 को ही नया विनियमन 10, जिसके आधार पर अपीलकर्ता का परिणाम प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया बताया गया था, भारत सरकार में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र.

यह तर्क देते हुए कि नया विनियमन अपीलकर्ता के मामले पर लागू नहीं हो सकता, श्री एम.एस. जैन ने आग्रह किया है-
(1) अपीलकर्ता, 9 सितंबर, 1966 से बहुत पहले प्री-इंजीनियरिंग कक्षा में शामिल हो गया था, जिस तारीख को विनियमन 10 में संशोधन का प्रस्ताव अकादमिक परिषद द्वारा शुरू किया गया था, पुराने विनियमन द्वारा शासित था और इसका हकदार था इसका लाभ;
(2) 14 जून, 1967 को, जब अपीलकर्ता का परिणाम घोषित किया गया था, तब नए विनियमन का सहारा नहीं लिया जा सकता था, 'क्योंकि उस समय तक संशोधित विनियमन लागू नहीं हुआ था, जैसा कि आवश्यक था, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। विनियम 22 द्वारा;
(3) चूंकि धारा 31 में कहा गया है कि नियम सरकार की मंजूरी से बनाए जाएंगे, इसलिए सीनेट के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था;

(4) विनियम 10 में किए गए संशोधन को अपीलकर्ता के नुकसान के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है;
(5) अपीलकर्ता द्वारा परीक्षा देने से पहले न तो नया विनियमन प्रकाशित किया गया था और न ही सीनेट द्वारा प्रस्तावित संशोधन को अपीलकर्ता या किसी परीक्षार्थी के ध्यान में लाया गया था; और
(6) कि, किसी भी मामले में, नए विनियमन में प्रयुक्त अभिव्यक्ति कि यह "1967 की परीक्षा से लागू होगी" के अर्थ को ध्यान में रखते हुए 1967 में आयोजित परीक्षाओं में इसके आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। शब्द "से" जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 में दिया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 1967 को बाहर रखा जाना है।

पंजाब विश्वविद्यालय-अधिनियम, 1947 की धारा 31 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो पहले पुन: प्रस्तुत किया गया है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के पास न केवल उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। मैट्रिक परीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय परीक्षा, बल्कि किसी भी नियम या विनियम या उपनियम में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करना। यह शक्ति, जैसा कि अधिनियम की धारा 31 में ही निर्धारित है, का प्रयोग केवल "सरकार की मंजूरी से" किया जा सकता है। चूँकि विनियम 10 में संशोधन, जिससे हम इस मामले में चिंतित हैं, पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद किया गया था, जब चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ी। माना जाता है कि दिसंबर, 1966 में सीनेट द्वारा विनियमन में संशोधन करने से पहले कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, और बाद में 11 जनवरी, 1967 को मंजूरी मांगी गई थी। प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा, जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित हुआ था, अप्रैल, 1967 के महीने में हुई थी। उसकी परीक्षा समाप्त होने के समय तक विनियमन 10 में प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई मंजूरी नहीं मिली थी, और यह 16 मई को थी, 1967, कि केंद्र सरकार ने उस तारीख के अपने पत्र द्वारा इसकी मंजूरी दे दी।
अधिनियम की धारा 31 के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया अध्याय IV में प्रदर्शित विनियमों में निहित है
पंजाब विश्वविद्यालय, कैलेंडर, 1967, खंड I, पृष्ठ 54। विनियम 21 का खंड (iii) प्रदान करता है: -
सीनेट द्वारा पारित विनियमों को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा और जब मंजूरी मिल जाएगी, तो विनियमों पर आम मुहर लगा दी जाएगी और उन्हें पंजाब-गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
विनियम 22 फिर कहता है:-

“22. कोई भी विनियमन राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा जब तक कि उसमें किसी अन्य तारीख को उस तारीख के रूप में नामित न किया जाए जिस तारीख को वह लागू होना है।

इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सीनेट द्वारा बनाए गए विनियमन के लागू होने या लागू होने से पहले, सरकार द्वारा इसकी मंजूरी धारा 31 के तहत प्राप्त की जानी चाहिए, और इसे विनियमन 22 में दिए गए अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया। राजपत्र में इसके प्रकाशन पर ही कोई विनियमन प्रभावी होता है। माना जाता है कि, जब अपीलकर्ता का परिणाम घोषित किया गया था, संशोधित विनियमन, जिसके आधार पर उसे प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में असफल घोषित किया गया था, प्रकाशित नहीं किया गया था, और इस प्रकार लागू नहीं था। एक ऐसे विनियमन का सहारा लेकर जो अभी तक लागू नहीं हुआ था, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया है क्योंकि वे इसके प्रवर्तन की प्रत्याशा में विनियमन को लागू करने में सक्षम नहीं थे। इस संक्षिप्त आधार पर अपीलकर्ता की रिट याचिका सफल होने की हकदार थी।

हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील, श्री एच.आर. सोढ़ी ने आग्रह करके विश्वविद्यालय अधिकारियों की कार्रवाई का बचाव करने का प्रयास किया है-

(1) विनियम 10 का संशोधन सीनेट द्वारा दिसंबर, 1966 में, अपीलकर्ता द्वारा अपनी परीक्षा देने से पहले अपनाया गया था और इस प्रकार 1967 में आयोजित परीक्षा पर लागू था;

(2) हालांकि अप्रैल में अपीलकर्ता की परीक्षा शुरू होने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं मिली थी। 1967, और संशोधित विनियमन 10 प्रकाशित किया गया था।

अगस्त, 1967, अपीलकर्ता का परिणाम घोषित होने के बाद, यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है ताकि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड I के पृष्ठ 54 पर दिखाई देने वाले विनियमन 22 के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य किया जा सके; और

(3) कि अपीलकर्ता के पास कोई निहित अधिकार नहीं था और वह इस बात पर जोर देने का हकदार नहीं था कि उसका परिणाम विनियम 10 के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए था क्योंकि यह संशोधन से पहले था।

श्री सोढ़ी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने पर, मैं उनके किसी भी तर्क को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। जैसा कि पहले देखा गया है, यह केवल अधिनियम की धारा 31 के तहत है कि विश्वविद्यालय की सीनेट को मैट्रिक परीक्षा के अलावा किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है।

यह सच है कि इस मामले में सीनेट ने अपीलकर्ता की परीक्षा शुरू होने से पहले दिसंबर, 1966 में विनियमन 10 के संशोधन को मंजूरी दे दी थी, और इसके द्वारा अनुमोदित संशोधित

विनियमन में, यह कहा गया था कि यह परीक्षा से प्रभावी होगा 1967 में, फिर भी तथ्य यह है कि अप्रैल 1967 में अपीलकर्ता की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला था कि संशोधित विनियमन को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, और बाद में, अपीलकर्ता का परिणाम घोषित होने के बाद, इस संशोधित विनियमन पर विचार किया गया। जिस आधार पर उसे फेल बताया गया है, वह प्रकाशित हो चुकी है।. चूँकि विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967 के खंड I के पृष्ठ 54 पर दिए गए उपनियम 22 में दिए गए प्रावधान के अनुसार यह केवल विनियम के प्रकाशन पर ही लागू होता है, इसलिए इसे इसके पहले परिणाम घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। राजपत्र में वास्तविक प्रकाशन जब इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था। श्री सोढ़ी का यह तर्क निस्संदेह सही है कि विनियम 22 के तहत भी, विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक विनियमन या नियम या उप-कानून जरूरी नहीं कि उसके प्रकाशन की तारीख पर लागू होगा, बल्कि किसी अन्य तारीख पर लागू होगा यदि ऐसी तारीख हो। उसमें निर्दिष्ट है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि एक प्रावधान जिसे स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी बनाया गया है, उसे लागू होने की तारीख से पहले लागू नहीं किया जा सकता है, और। कानून के अनुसार प्रख्यापित होने के बाद ही आईसी पूर्वव्यापी रूप से संचालित होगी।

इसके अलावा, मुझे लगता है कि 5 अगस्त 1967 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित विनियमन में ऐसी कोई विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं है। यह केवल विनियम के पाद-नोट में कहा गया है:
"1967 की परीक्षा से प्रभावी होना"। मेरी राय है कि फ़ुट-नोट को स्वयं विनियमन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसमें विनियमन के समान बल नहीं है। विनियम 10, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को असफल घोषित किया गया था, 5 अगस्त, 1967 को ही लागू माना जाना चाहिए, जब इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और चूंकि इसे प्राप्त नहीं किया गया था। जब अपीलकर्ता ने अपनी परीक्षा दी थी तब तक केंद्र सरकार की सहमति और अपीलकर्ता के परिणाम घोषित होने से पहले इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, इसे अपीलकर्ता के मामले में उसके नुकसान के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। चूँकि अपील केवल इसी आधार पर सफल होनी चाहिए, हम इस सवाल से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं कि क्या विश्वविद्यालय प्राधिकारी किसी विशेष परीक्षा के लिए अध्ययन की अवधि के दौरान किसी उम्मीदवार के नुकसान के लिए विनियम में संशोधन कर सकते हैं और क्या नियम बनाने वाला प्राधिकारी अपने द्वारा बनाए गए किसी नियम को कानून द्वारा प्रदत्त ऐसी शक्ति के बिना पूर्वव्यापी प्रभाव दे सकता है।
परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार कर ली जाती है, और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए, हम अपीलकर्ता के आक्षेपित परिणाम को रद्द कर देते हैं और निर्देश देते हैं कि उसका परिणाम विनियम 10 के आधार पर घोषित किया जाए जैसा कि संशोधन प्रकाशित होने से पहले था। अगस्त 1967 के सरकारी राजपत्र में।

डी. आर. महाजन, जे.- मैं सहमत हूं।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा